राष्ट्रीय संस्करण

वर्ष 3 अंक 102

मूल्य ₹6.00, नई दिल्ली, शुक्रवार, 20 सितंबर 2019

दैनिक जागरण

www.jagran.com

पृष्ठ 16

जादवपुर विवि में केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो पर हमला >>7

राम की खातिर देश की न्याय प्रणाली पर भरोसा रखें : मोदी

बरसे पीएम ▶ कहा – राम मंदिर के मामले में चुप ही रहें 'बयान बहादुर' और 'बड़बोले' लोग

सर्वोच्च न्यायालय लगातार समय निकालकर सुन रहा है हर पक्ष की बात

ओमप्रकाश तिवारी, नासिक

सुप्रीम कोर्ट में राम जन्मभूमि मसले पर सुनवाई जारी रहते राम मंदिर पर टीका-टिप्पणी करने वालों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जमकर फटकार लगाई है। ऐसे 'बयान बहादुरों' को उन्होंने देश की न्याय प्रणाली एवं सर्वोच्च न्यायालय पर भरोसा रखने की नसीहत दी है।

प्रधानमंत्री गुरुवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस की महाजनादेश यात्रा के समापन पर नासिक में एक रैली को संबोधित कर रहे थे। इसी कड़ी में नासिक से प्रभु राम के जुड़ाव का उल्लेख करने के बाद उन्होंने राममंदिर पर बयान देने वालों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, 'मैं देख रहा हूं कि पिछले दो-तीन सप्ताह से कुछ 'बयान बहादुर' और 'बड़बोले' लोग राममंदिर निर्माण को लेकर अनाप-शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। जब मामला सर्वोच्च न्यायालय में चल रहा है। सभी पक्ष अपनी बात रख रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय लगातार समय निकालकर सभी की बात सुन रहा है। तो मैं हैरान हूं कि ये 'बयान बहादुर' कहां से टपक गए!' प्रधानमंत्री ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय और बाबासाहेब आंबेडकर के बनाए संविधान पर हमारा भरोसा होना चाहिए। उन्होंने आगे कहा, 'आज नासिक की पवित्र धरती से मैं देशभर में, ये जो बड़बोले लोग हैं, बयान बहादुर हैं, उनसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि भगवान की खातिर, प्रभु राम की खातिर भारत की न्याय प्रणाली के प्रति श्रद्धा रखें।' उल्लेखनीय है कि दो दिन पहले ही शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने संसद में कानून बनाकर राममंदिर निर्माण की वकालत की थी। उन्होंने दावा किया था कि मंदिर की पहली ईंट शिवसैनिक ही रखेगा।

कश्मीर को स्वर्ग बनाना है : मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस के भाषण के दौरान सामने बैठे श्रोता 'कश्मीर हमारा है' का नारा लगा रहे थे। प्रधानमंत्री ने इसी नारे का उल्लेख करते हुए कहा कि अब हर हिंदुस्तानी को नारा लगाना है कि हमें कश्मीर को स्वर्ग बनाना है।

महाराष्ट्र के नासिक में गुरुवार को 'विजय संकल्प रैली' के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रेट्र

उन्होंने कहा, '40 साल तक 42000 लोगों को जिस धरती पर मौत के घाट उतार दिया गया। उस धरती को 130 करोड़ देशवासी एक बार फिर स्वर्ग बनाकर रहेंगे। आप सब कश्मीर की भलाई के लिए आगे आएं। मेरी इच्छा है कि आप कश्मीरवासियों के घावों पर मरहम लगाने के लिए आगे आएं। अब तक दिल्ली की गलत नीतियों के वे शिकार हुए हैं। देश का काम है कि उन्हें उन मुसीबतों से मुक्ति दिलाए।'

देशवासियों से किया वादा पूरा किया : प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, 'लोकसभा चुनाव से पहले हमने वायदा किया था कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख की समस्याओं के समाधान की कोशिश करेंगे। आज मैं संतोष के साथ कह सकता हूं कि देश उन सपनों को साकार करने की दिशा में चल पड़ा है।' उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर में भारत के संविधान को समग्रता से लागू करना सिर्फ एक सरकार का फैसला नहीं है। यह 130 करोड़ भारतीयों की भावनाओं का प्रकटीकरण है। यह फैसला जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लोगों को हिंसा, आतंक और भ्रष्टाचार के कुचक्र से बाहर निकालेगा। यह भारत की एकता और अखंडता के लिए हमारी प्रतिबद्धता तो थी ही, अब यह जम्मू-कश्मीर के लोगों की आकांक्षाओं और सपनों की पूर्ति का माध्यम भी बनने वाला है। उल्लेखनीय है कि कश्मीर में प्रशासन की ओर से स्थानीय लोगों को तमाम रियायतें दी जा रही हैं। तमाम पाबंदियों को भी हटा दिया गया है।

शरद पवार पर बोला हमला

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार को आड़े हाथों लेते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, 'कांग्रेस का कन्फ्यूजन समझा जा सकता है लेकिन पवार साहब, जब आप जैसा अनुभवी नेता भी वोट के लिए गलतबयानी करने लगे, तो बड़ा दुख होता है।' मोदी ने कहा, 'शरद पवार जी को पड़ोसी देश अच्छा लगता है, यह उनकी मर्जी। वहां के शासक उनको कल्याणकारी लगते हैं, यह भी उनका आकलन है। पूरा महाराष्ट्र, पूरा देश, यहां तक कि पूरी दुनिया जानती है कि आतंक की फैक्ट्री कहां पर है और जुल्म व शोषण की तस्वीरें कहां से आती हैं। राजनीति में नेताओं और दलों की जीत-हार होती रहती है, लेकिन देश को जिताना हम सभी का दायित्व है।'

विपक्ष पर भी साधा निशाना

प्रधानमंत्री मोदी ने जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के विरोध पर भी विपक्ष को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा, 'देश का हर वर्ग, युवा-बुजुर्ग, शहर-गांव इस फैसले में देश के साथ है। लेकिन दुर्भाग्य से कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को जैसा सहयोग देना चाहिए, वह नहीं दिखाई दे रहा है। विपक्ष के नाते वह हमारी आलोचना करें, देवेंद्र फड़नवीस की आलोचना करें। यह उनका अधिकार है। लेकिन ऐसी बात करना कि विदेशों में उनके बयानों के आधार पर भारत पर हमला हो, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे लोगों को पहचानने की जरूरत है।'

सरोकार

सरकारी स्कूलों को संवार रहा इस पेंटर का जुनून

बदायूं : उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले के पेंटर मुस्तफा अब्बासी अपनी सोच और जज्बे के कारण खास पहचान बना चुके हैं। दीवारों पर उनके द्वारा उकेरे गए प्रेरक चित्रों ने बदायूं के स्कूलों को भी खास बना दिया है। वह अपनी कमाई का एक हिस्सा भी स्कूलों की बेहतरी में खर्च करते हैं। (पेज-10)

जागरण विशेष

दूध और शैवाल से बने ईंधन से दौड़ेंगे वाहन

सोलन : दुग्ध संयंत्र के कचरे व शैवाल के मिश्रण से ऐसा जैव ईंधन तैयार किया गया है, जो पेट्रोल या डीजल का विकल्प हो सकेगा। शूलिनी विवि में इस बायो फ्यूल से इंजन चलाया गया। प्रयोग यह अंतरराष्ट्रीय मानकों पर भी खरा उतरा है। (पेज-10)

न्यूज गैलरी

राज-नीति ▶ पृष्ठ 3

मंजूरी बाद ही कालेधन की सूचना साझा करें : सीबीडीटी

नई दिल्ली : केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने कहा है कि आयकर विभाग द्वारा विदेशी कालेधन की जांच में विदेशी कर संधियों के जरिये हासिल जानकारियां गोपनीय हैं और उन्हें संबंधित देशों से सहमति हासिल करने के बाद ही ईडी और सीबीआइ जैसी एजेंसियों के साथ साझा किया जा सकता है।

नेशनल न्यूज ▶ पृष्ठ 7

राजीव की गिरफ्तारी के लिए निर्देश की जरूरत नहीं : कोर्ट

कोलकाता : सारधा कांड में कोलकाता के पूर्व पुलिस आयुक्त राजीव कुमार के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी करने के लिए दायर याचिका पर गुरुवार को अलीपुर कोर्ट ने फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा, राजीव कुमार के लिए गिरफ्तारी वारंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उन पर संगीन आरोप लगे हैं।

बिजनेस ▶ पृष्ठ 12

अमेरिकी कंपनियों के सामने मोदी रखेंगे भारत का एजेंडा

नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 सितंबर को अमेरिका की यात्रा पर पहुंच रहे हैं। सात दिनी दौरे में उनका मुख्य फोकस कारोबार से जुड़े मुद्दों का समाधान निकालने व निवेश बढ़ाने पर होगा। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनकी द्विपक्षीय वार्ता रणनीतिक लिहाज से अहम होगी। ट्रंप के अलावा भी मोदी की 45 छोटे-बड़े देशों के प्रमुखों के साथ अलग से बैठक होगी।

आजकल ▶ पृष्ठ 16

नासा के यान ने खींची विक्रम की लैंडिंग साइट की तस्वीर

ह्यूस्टन : अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के एलआरओ यान ने 17 सितंबर को चांद के दक्षिणी ध्रुव की ओर से गुजरते समय भारत के चंद्रयान-2 के लैंडर विक्रम की लैंडिंग साइट की तस्वीर खींची है। एजेंसी अभी इन तस्वीरों का विश्लेषण कर रही है। इसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि इनमें विक्रम की तस्वीर है या नहीं। तस्वीरों से विक्रम की स्थिति को लेकर भी जानकारी सामने आ सकती है।

अमित शाह से मिलीं ममता, उठाया असम में एनआरसी का मुद्दा

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- बोलीं, बंगाल में एनआरसी पर नहीं हुई बात
- कहा, छूटे 19 लाख लोगों को भी सूची में करें शामिल

बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने गुरुवार को अमित शाह से भेंट की। शाह के गृह मंत्री बनने के बाद उनसे ममता की यह पहली भेंट थी। एएनआइ

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बुधवार को मुलाकात के बाद गुरुवार को बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अमित शाह से मिलने गृह मंत्रालय पहुंचीं। शाह के गृहमंत्री बनने के बाद यह ममता की उनसे पहली मुलाकात थी। इस दौरान उन्होंने असम में जारी राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) का मुद्दा उठाया। ममता का कहना है कि एनआरसी में बहुत सारे गोरखा, हिंदी भाषी, बिहारी और असम के निवासियों के नाम नहीं हैं। सरकार को इन्हें एनआरसी में शामिल करने के लिए उचित कदम उठाना चाहिए।

मुलाकात के बाद ममता ने कहा, असम में एनआरसी को लेकर उन्होंने गृहमंत्री को पत्र दिया है। राज्य में एनआरसी में जो 19 लाख मतदाता छूट गए हैं वे परेशान और डरे हुए हैं। इन लोगों को एनआरसी में शामिल करने का मौका मिलना चाहिए। ममता के अनुसार, अमित शाह ने उनकी बातें ध्यान से सुनीं और उन पर गौर करने का भरोसा दिया। मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि गृहमंत्री इस दिशा में सकारात्मक भूमिका अदा करेंगे। ज्ञात हो, खुद अमित शाह और भाजपा भी एनआरसी की पूरी प्रक्रिया से संतुष्ट नहीं है। यही कारण है कि असम सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में भी आग्रह किया गया था कि तिथि बढ़ाई जाए। अभी भी राज्य सरकार की ओर से मांग की जा रही है कि सीमावर्ती क्षेत्रों में 20 फीसद जनसंख्या की समीक्षा की जाए। खुद शाह एक दिन पहले ही कह चुके हैं कि पूरे देश में एनआरसी को लागू किया जाएगा।

ममता बोलीं-बंगाल में एनआरसी की जरूरत नहीं : मीडिया के सम्मुख ममता ने कहा, बंगाल में एनआरसी की कवायद की जरूरत नहीं है, लेकिन उन्होंने दावा किया कि अमित शाह से भेंट के दौरान बंगाल में एनआरसी को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई। इसके साथ ही उन्होंने यह साफ कर दिया कि राजग सरकार के घटक दल जद यू के नेता और बिहार के मुख्यमंत्री नीतिश कुमार भी अपने राज्य में एनआरसी की जरूरत को खारिज कर चुके हैं।

राजीव कुमार पर भी साधी चुप्पी : ममता बनर्जी ने मुलाकात के दौरान कोलकाता के पूर्व कमीशनर और वरिष्ठ आइपीएस अधिकारी राजीव कुमार का मुद्दा उठने के बारे में भी कुछ नहीं बताया। गौरतलब है कि कोलकाता हाईकोर्ट से गिरफ्तारी पर रोक हटने के बाद से ही सीबीआइ राजीव कुमार को ढूंढ रही है, जबकि पहले राजीव कुमार से पूछताछ को लेकर कोलकाता पुलिस और सीबीआइ आमने-सामने आ गई थीं।

वाड्रा को हरियाणा सरकार ने दिया झटका, रद होगा स्काई लाइट हॉस्पिटेलिटी का लाइसेंस

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़

- राज्य के टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग ने पूरी की औपचारिकताएं
- सरकार से साढ़े सात करोड़ में भूमि लेकर डीएलएफ को 58 करोड़ में बेची थी

हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए खड़ा होने की कोशिश कर रही कांग्रेस को तगड़ा झटका लगने वाला है। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग ने कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी स्काई लाइट हॉस्पिटेलिटी प्राइवेट लिमिटेड को वर्ष 2008 में दिया गया रियल एस्टेट डेवलपमेंट लाइसेंस रद करने की तैयारी कर ली है। औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं और किसी भी समय आदेश जारी हो सकता है।

पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में स्काई लाइट को गुरुग्राम के शिकोहपुर गांव (सेक्टर-83) में 3.53 एकड़ जमीन साढ़े सात करोड़ रुपये में कॉलोनी डेवलप करने के लिए दी गई थी। सरकार ने इसमें 2.70 एकड़ भूमि को व्यावसायिक कॉलोनी के तौर पर विकसित करने की मंजूरी देते हुए लाइसेंस वाड्रा की कंपनी को दिया था। स्काई लाइट ने कॉलोनी विकसित करने की बजाय 18 सितंबर 2012 को 58 करोड़ में यह जमीन डीएलएफ यूनिवर्सल लिमिटेड को बेच दी। तब भी हुड्डा की सरकार थी। स्काई लाइट ने सेल डीड के

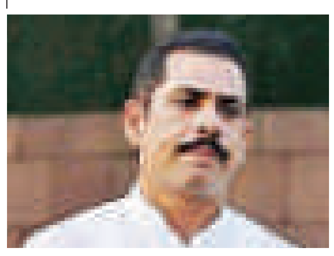

रॉबर्ट वाड्रा — फाइल फोटो

जरिये जमीन बेच दी, लेकिन टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग ने लाइसेंस को ट्रांसफर करने की अंतिम मंजूरी नहीं दी थी। डीएलएफ वर्ष 2018 तक रिन्यूअल फीस जमा कराती रही, लेकिन इसके बाद लाइसेंस नवीनीकरण के लिए आवेदन नहीं किया गया है। इसे आधार बनाते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वाड्रा की कंपनी को वर्ष 2008 में दिया गया रियल एस्टेट डेवलपमेंट लाइसेंस रद करने का निर्देश दिया है।

प्रवर्तन निदेशालय ने गुरुग्राम जमीन घोटाले में स्काई लाइट हॉस्पिटेलिटी के खिलाफ पहले ही एफआइआर दर्ज कर रखी है। पिछले साल गुरुग्राम पुलिस ने रॉबर्ट वाड्रा, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और डीएलएफ के खिलाफ अलग से एफआइआर दर्ज की थी।

यह है लाइसेंस रद करने का आधार : टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के निदेशक केएम पांडुरंग के मुताबिक हरियाणा विकास और शहरी क्षेत्रों के विनियमन अधिनियम 1975 के प्रावधानों के अनुसार लाइसेंस रद करने की औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं। वर्ष 2012 में तत्कालीन महानिदेशक अशोक खेमका ने इस जमीन का म्यूटेशन रद कर दिया था। अधिनियम की शर्तों के मुताबिक लाइसेंस धारक के पास भूमि का स्पष्ट शीर्षक होना चाहिए। एक उपनिवेशक लाइसेंस धारक को आवासीय, वाणिज्यिक या औद्योगिक उद्देश्यों के लिए एक कॉलोनी स्थापित करने की अनुमति देता है।

खेमका ने उजागर किया था घोटाला पेज>>7

आर के एस भदौरिया होंगे अगले वायुसेना प्रमुख

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

एयर मार्शल आर.के. एस भदौरिया नए वायुसेना प्रमुख होंगे। वह मौजूदा वायुसेना प्रमुख बीएस धनोआ का स्थान लेंगे, जो 30 सितंबर को रिटायर होने जा रहे हैं। भदौरिया ने मई में वायुसेना के उप-प्रमुख का पद ग्रहण किया था। रक्षा मंत्रालय के मुख्य प्रवक्ता ने ट्विटर पर कहा है, 'सरकार ने एयर मार्शल आरकेएस भदौरिया (पीवीएसएम, एवीएसएम, वीएम, एडीसी) को अगला वायुसेना प्रमुख नियुक्त करने का फैसला लिया है।' नेशनल डिफेंस अकादमी से जुड़े रहे भदौरिया जून 1980 में वायुसेना के लड़ाकू दस्ते में शामिल हुए थे। 'सोर्ड ऑफ ऑनर' के साथ ही वह परम विशिष्ठ सेवा पदक, अति विशिष्ठ सेवा पदक से अलंकृत हो चुके हैं। भदौरिया की राफेल सौदे में भी अहम भूमिका थी। वह 26 प्रकार के लड़ाकू और परिवहन विमानों को

उड़ा चुके हैं। 40 वर्षों की सेवा में भदौरिया ने जगुआर स्क्वाड्रन और एक प्रमुख वायुसैनिक अड्डे को कमांड कर चुके हैं। वह हल्के लड़ाकू विमान (एलसीए) परियोजना पर राष्ट्रीय उड़ान परीक्षण केंद्र के परियोजना निदेशक और मुख्य प्रशिक्षक पायलट रह चुके हैं। रोचक बात यह है कि एयर मार्शल भदौरिया भी 30 सितंबर को रिटायर होने वाले थे, लेकिन अब वह वायुसेना प्रमुख पद पर नियुक्त किए गए हैं तो माना जा रहा है अगले दो साल तक वह इस पद पर रहेंगे।

---

400 जिलों में 'शामियाना' लगाकर बंटेगा कर्ज

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- पहले चरण में 29 तक 200 जिलों में एनबीएफसी व जनता को मिलेगा लोन
- एमएसएमई के बकाये कर्ज मार्च, 2020 तक नहीं बदले जाएंगे एनपीए में

बाजार में मांग बढ़ाने के लिए त्योहारी सीजन में ज्यादा से ज्यादा कर्ज मुहैया कराने के फॉर्मूले को सरकार इस बार भी आजमाने जा रही है। इसमें सरकारी क्षेत्र के बैंकों की भूमिका सबसे अहम होगी। इन बैंकों के प्रमुखों के साथ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को बैठक की, जिसमें अगले 20 दिनों में देश के 400 जिलों में 'शामियाना फॉर्मूले' के तहत कर्ज बांटने का फैसला किया गया। कर्ज आम जनता को भी दिया जाएगा और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) को भी ताकि वे भी होम, ऑटो लोन व अन्य लोन वितरित कर सकें।

वित्त मंत्रालय की तरफ से बैंकों को निर्देश दिया गया है कि वे दो चरणों में 400 जिलों को पर्याप्त कर्ज बांटें। पहला चरण 29 सितंबर, 2019 तक होगा जिसमें 200 जिलों में बैंकों की तरफ से कर्ज वितरण के विशेष कार्यक्रम चलाए जाएंगे। दूसरा चरण 10 अक्टूबर 2019 तक लागू होगा। कर्ज वितरण के लिए बैंकों

नई दिल्ली में गुरुवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की समीक्षा बैठक में हिस्सा लेने के बाद प्रेसवार्ता की। प्रेट्र

की तरफ से शिविर लगाए जाएंगे और उसमें एनबीएफसी के साथ ही आम जनता को भी बुलाया जाएगा। चूंकि यह अस्थायी ढांचा होगा इसलिए इसका नाम शामियाना फॉर्मूला रखा गया है। वित्त मंत्री ने बताया कि, 'बैंकों से कहा गया है कि वे नए ग्राहकों की तलाश करें। हर एक पुराने ग्राहक पर पांच नए ग्राहक खोजने का काम उन्हें करना होगा। कोशिश यह होगी कि जिन्हें कर्ज की जरूरत है उन्हें बिना किसी देरी के कर्ज मिले। बैंकों की तरफ से कई एनबीएफसी की पहचान हो चुकी है जिन्हें वह कर्ज देंगे।'

सीतारमण ने बताया, 'बैंकों से कहा गया है कि वे जुलाई-सितंबर के दौरान पुराने कर्जे के एकमुश्त निबटारे के काम को तेज करें। एमएसएमई को एकमुश्त निबटारे की सुविधा दी जाए।' बैंकों से कहा गया है कि एमएसएमई के बकाये कर्ज को 30 मार्च, 2020 तक एनपीए घोषित नहीं किया जाए। त्योहारी सीजन में सबसे ज्यादा कर्ज ऑटो व आवास के लिए लिया जाता है और इन दोनों सेक्टरों की हालत काफी खराब है। बैंक पहले ही कह चुके हैं कि उनके पास एक लाख करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि है जिसे वह कर्ज के तौर पर दे सकते हैं।

आरबीआइ ने कहा, रेपो रेट में एक और कटौती की गुंजाइश पेज>>12

तेजस में उड़ान भरने वाले पहले रक्षा मंत्री बने राजनाथ

नई दिल्ली : रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्वदेश में निर्मित हल्के लड़ाकू विमान तेजस (एलसीए) में गुरुवार को बेंगलुरु स्थित एचएएल हवाई अड्डे से उड़ान भरी। इसी के साथ राजनाथ सिंह तेजस लड़ाकू विमान में उड़ान भरने वाले पहले रक्षा मंत्री बन गए। हवाई सफर के बाद उन्होंने कहा कि विमान में सफर का उनका अनुभव रोमांचक रहा। सिंह ने विमान से उतरने के बाद अपनी उड़ान को सहज और आरामदायक बताया। (पेज-3)

सबसे ज्यादा बेनामी संपत्तियां मध्य प्रदेश में खरीदी गईं

भोपाल : देश में कालेधन से बेनामी संपत्तियां खरीदने के मामले में आयकर विभाग ने मध्य प्रदेश को शीर्ष पर पाया है। विभाग की बेनामी यूनिट ने यहां सबसे ज्यादा संपत्तियां अटैच (कुर्क) की हैं। पिछले वित्त वर्ष तक 300 से अधिक ऐसी संपत्तियां अटैच की गईं, जो फर्जी नामों से खरीदी गई थीं। अब तक 200 संपत्तियां छानबीन के दायरे में ली गई हैं। (पेज-7)

अड़ंगा खत्म

गुजरात हाई कोर्ट की खंडपीठ ने कहा, राज्य को भूमि अधिग्रहण का अधिकार, किसान चाहें तो अधिक मुआवजे के लिए राज्य सरकार से कर सकते हैं अपील

बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की राह हुई आसान

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- भूमि अधिग्रहण के खिलाफ सभी याचिकाएं गुजरात हाई कोर्ट ने खारिज कीं

गुजरात हाई कोर्ट ने अहमदाबाद-मुंबई बुलेट ट्रेन परियोजना में भूमि अधिग्रहण के खिलाफ किसानों की ओर से दाखिल सभी 120 याचिकाओं को खारिज कर दिया है। इससे अब परियोजना के काम में तेजी आने की उम्मीद बढ़ी है। हालांकि किसान अब सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की बात कर रहे हैं।

जस्टिस एएस दवे की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा किसानों के लिए प्रस्तावित मुआवजे की रकम उचित है। यदि किसान चाहें तो मुआवजा बढ़ाने के लिए राज्य सरकार से अपील कर सकते हैं। पीठ ने गुजरात सरकार द्वारा 2016 में केंद्रीय भूमि अधिग्रहण कानून में किए गए संशोधन के साथ केंद्र द्वारा राज्य को पूर्व प्रभाव से भूमि अधिग्रहण करने के दिए गए कार्यकारी अधिकार को भी वैध बताया।

कोर्ट की राय थी कि संशोधित एक्ट में सामाजिक प्रभाव आकलन (सोशल इंपैक्ट असेसमेंट-एसआइए) का प्रावधान न किया जाना 'अधिकार के बेजा इस्तेमाल' की श्रेणी में नहीं आता। क्योंकि एसआइए की प्रक्रिया जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी (जिका) के दिशानिर्देशों के तहत निर्धारित की गई है। बहरहाल, किसानों के वकील आनंद याज्ञिक ने हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का एलान किया है। उन्होंने कहा कि बुलेट ट्रेन परियोजना से तकरीबन 5,900 किसान प्रभावित हुए हैं। इनमें से लगभग 60 फीसद किसानों ने भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया का विरोध किया था।

पिछले वर्ष सूरत जिले के पांच किसानों ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर भूमि अधिग्रहण के लिए गुजरात सरकार द्वारा जारी अधिसूचना की वैधता पर सवाल उठाए थे। उनका दावा था कि 508 किलोमीटर लंबी परियोजना का विस्तार कई राज्यों में है लिहाजा केवल केंद्र सरकार को अधिसूचना जारी करने का अधिकार है। इन पांच किसानों ने बाद में अपनी याचिका वापस ले ली। परंतु उसके बाद दक्षिण व मध्य गुजरात के विभिन्न जिलों के सैकड़ों अन्य किसानों ने हाई कोर्ट में याचिकाएं दाखिल कर गुजरात सरकार के अधिकार को नए सिरे से चुनौती दी। सुनवाई होते-होते किसानों की संख्या बढ़कर करीब एक हजार हो गई। इन सबका कहना था कि उन्हें सोशल इंपैक्ट असेसमेंट एवं बाजार कीमतों के अनुसार अधिक मुआवजा मिलना चाहिए। परंतु रेलवे का तर्क था कि केंद्र ने राष्ट्रपति की मंजूरी से राज्य सरकार को भूमि अधिग्रहण का अधिकार दिया है, लिहाजा यह पूरी तरह वैध है।

अहमदाबाद-मुंबई बुलेट ट्रेन परियोजना देश की पहली हाईस्पीड रेल परियोजना है, जिसे जापान के सहयोग से कार्यान्वित किया जा रहा है। लगभग 1.10 लाख करोड़ रुपये लागत के इस प्रोजेक्ट में लगभग 88 हजार करोड़ रुपये की रकम जापान बेहद सस्ते कर्ज के रूप में प्रदान कर रहा है। 14 सितंबर, 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री एबी शिंजो ने परियोजना का भूमि पूजन किया था। इसे 2023 तक पूरा करने का लक्ष्य है। 250 किमी की औसत रफ्तार पर चलने वाली बुलेट ट्रेन में दो श्रेणियां होंगी। जिनका किराया राजधानी से लगभग डेढ़ गुना होगा।

उत्तर प्रदेश में पॉक्सो एक्ट में पहला मृत्युदंड

आगरा : बेटी से दरिंदगी कर उसकी गला दबाकर हत्या करने वाले पिता को गुरुवार को अपने किए की सजा मिल गई। विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावी क्षेत्र वीके जायसवाल ने एक वर्ष दस माह की सुनवाई के बाद उसे दोषी करार दे दिया। मामले को विरलतम (रेयरेस्ट ऑफ द रेयर) मानते हुए अदालत ने दोषी पिता को मृत्युदंड दे दिया। उप्र में पॉक्सो एक्ट (यौन अपराध शिशु संरक्षण अधिनियम) के तहत मृत्युदंड का यह पहला मामला है। (पेज-5)

ईरान की 'युद्ध' की चेतावनी के बाद ढीले पड़े अमेरिका के तेवर

आबू धाबी : सऊदी अरब के तेल संयंत्रों पर हमले के बाद ईरान पर हमले की धमकी दे रहे अमेरिका के तेवर गुरुवार को ढीले पड़ गए। ईरान ने चेतावनी दी है कि उस पर किसी भी तरह के हमले की परिणाम पूर्ण युद्ध के रूप में सामने आ सकता है। इसके बाद सऊदी अरब पहुंचे अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोंपियो ने कहा कि वह चाहेंगे कि संकट को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझा लिया जाए। (पेज-13)

व्यावसायिक वाहनों की हड़ताल का दिखा मिलाजुला असर

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

- रेलवे स्टेशनों, बस अड्डे व एयरपोर्ट पर पेश आई परेशानी
- नए मोटर वाहन कानून में भारी जुर्माने के विरोध में की हड़ताल

नए मोटर वाहन कानून में भारी जुर्माने, आरएफआइडी टैग की अनिवार्यता समेत अन्य मुद्दों को लेकर व्यावसायिक वाहनों की हड़ताल का दिल्ली में मिलाजुला असर दिखा। सड़कों पर एप आधारित कैब, ऑटो, स्कूल बस व टैक्सी समेत अन्य वाहनों की संख्या में आम दिनों के मुकाबले 40 फीसद तक कमी दिखी। रेलवे स्टेशनों, बस अड्डे व एयरपोर्ट पर यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा।

दिल्ली के कई स्कूलों ने हड़ताल को देखते हुए गुरुवार को छुट्टी कर दी थी। कई लोगों ने ऑफिस मीटिंग और घूमने-फिरने के प्लान को स्थगित किया। अक्षरधाम, कुतुबमीनार, नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशनों समेत कई स्थानों पर वाहनों को रोकने और जबरदस्ती सवारियों को उतारा गया। आनंद विहार में कुछ वाहनों में तोड़फोड़ भी की गई। चल रहे कैब व ऑटो चालकों ने मनमाना किराया वसूला।

यूनाइटेड फ्रंट ऑफ ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के महासचिव श्याम लाल गोला ने कहा, हड़ताल पूर्णतया सफल रही। कुछ दिन तक केंद्र व राज्य सरकार के रुख का इंतजार किया जाएगा। सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिली तो राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन किया जाएगा। दिल्ली टैक्सी, टूरिस्ट, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन समेत कुछ अन्य संगठन हड़ताल में शामिल नहीं हुए थे, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने उन्हें वाहन नहीं चलाने दिए।

डीटीसी की बसों और मेट्रो ने दिया सहारा : डीटीसी की बसों और मेट्रो ने लोगों को बड़ा सहारा दिया। हालांकि डीटीसी की बसों में ज्यादा भीड़ नहीं थी क्योंकि दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) ने सभी बसों को सड़क पर उतारते हुए अधिकाधिक परिचालन किया।